कोलकाता, शुक्रवार, 03 .05 .2019

बड़ी कूटनीतिक जीत

सुरक्षा परिषद् द्वारा जैशे-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किया जाना भारतीय कूटनीति की महत्वपूर्ण उपलब्धि है. हालांकि, उसके गिरोह को 2001 में ही आतंकी सूची में डाल दिया था तथा 2009 में भारत ने भी अजहर को आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव दिया था, किंतु अंतरराष्ट्रीय राजनीति की खींचतान और चीन के अड़ियल रवैये के कारण वह बचता रहा था. पुलवामा हमले के बाद भारत ने इस दिशा में ठोस पहलें की और चीन को भी भरोसे में लेने की कोशिश हुई. कुछ दिन पहले विदेश सचिव विजय गोखले ने ठोस दस्तावेजों के आधार पर मसूद अजहर के खतरनाक हरकतों से चीनी नेतृत्व को अवगत कराया था. चीन ने भी अपने रुख में बदलाव के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि ऐसा नये सबूतों के कारण हुआ है. भारतीय प्रयासों के कारण ही फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका न सिर्फ प्रस्ताव लेकर आये, बल्कि उन्होंने यह भी कह दिया था कि अगर सुरक्षा परिषद् में प्रस्ताव फिर से रुक जाता है, तो वे इस मसले पर खुली चर्चा करायेंगे. इससे भी चीन पर दबाव बढ़ा, क्योंकि ऐसी कोई भी चर्चा उसे अलग-थलग कर सकती थी. कई सालों से भारत विभिन्न मंचों पर और द्विपक्षीय बातचीत में देशों को पाकिस्तान-समर्थित आतंकी गिरोहों के बारे में कहता रहा है. मसूद अजहर, सैयद सलाहुद्दीन, हाफिज सईद जैसे सरगना कश्मीर समेत भारत में अलग-अलग जगहों पर आतंकी हमलों को अंजाम देते रहे हैं. इनसे जुड़े चरमपंथी और हिंसक गिरोह अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और ईरान में भी सक्रिय हैं. पाकिस्तान से अपनी गतिविधियों के संचालन करने के बावजूद इन्होंने वहां की जनता को भी अपना शिकार बनाया है. सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव में मसूद अजहर के अल-कायदा और तालिबान से गठजोड़ को रेखांकित किया गया है. बालाकोट में भारतीय वायु सेना की कार्रवाई पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई आलोचना न होने से भी यह इंगित हुआ था कि दुनिया में आतंक को लेकर एक आम राय बन रही है तथा भारत की ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है. चीन द्वारा इस प्रस्ताव पर सहमत होने से भारत के साथ उसके संबंधों पर भी सकारात्मक असर होने की उम्मीद है. यह दोनों देशों के आर्थिक एवं सुरक्षा हितों के लिए शुभ संकेत है. लेकिन, यह भी ध्यान रखना होगा कि मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कराना आतंक के विरुद्ध लड़ाई में एक कदम ही है, क्योंकि पहले की पाबंदियों के बावजूद विभिन्न गिरोह हमलावर होते रहे हैं. ऐसे में सबसे जरूरी है कि पाकिस्तान पर पूरी दुनिया दबाव बनाये कि वह आतंक को शह देना बंद करे. अक्सर ताकतवर देश अपने हितों के कारण आतंकवाद पर दोहरा मानदंड अपनाते हैं. इससे उन्हें बड़ा नेटवर्क बनाने में मदद मिलती है. यह वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है. आतंकवाद के विरुद्ध व्यापक अंतरराष्ट्रीय एकजुटता आवश्यक है और सुरक्षा परिषद् का निर्णय इस दिशा में एक बड़ी पहल है.

आतंकवाद के विरुद्ध व्यापक अंतरराष्ट्रीय एकजुटता आवश्यक है और मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कर सुरक्षा परिषद् ने इस दिशा में एक बड़ी पहल है.

जापान के नये सम्राट से उम्मीद

तरुण विजय
वरिष्ठ भाजपा नेता
tarunvijay55555@gmail.com

जापान से आज हमारे जिस तरह के संबंध हैं, वैसे शायद ही किसी अन्य देश से हों. नये सम्राट नारूहितों के साथ भारतीय जनता और विचारकों के संबंध प्रगाढ़ हों, यह हमारे राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों के बढ़ने से भी ज्यादा जरूरी है.

जापान से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जापान एक ऐसा देश है, जो अपनी परंपराओं की रक्षा और निर्वाह बखूबी करता है. भारत में यदि कोई प्राचीन परंपराओं को संभालने की बात करता है, तो उनके बारे में यह कहा जाता है कि ये लोग अतीतजीवी हैं. ऐसे लोग यह बात नहीं समझते कि भविष्योन्मुखी होने के लिए अतीत को त्यागना या उसका अपमान करना जरूरी नहीं है. ये लोग जापान को नहीं देखते, जिसने यह बात सिद्ध करके दिखायी है. जापान में ढाई हजार साल से भी पुरानी राजवंशीय परंपरा आज भी फल-फूल रही है तथा बीते 30 अप्रैल को वहां के सम्राट अकिहितो ने 85 वर्ष की आयु में अपने स्वास्थ्य कारणों से सिंहासन त्याग कर दिया और अगले दिन यानी एक मई, 2019 को उनके 59 वर्षीय पुत्र राजकुमार नारूहितो ने जापान के 126वें सम्राट के रूप में पद संभाला. इसके साथ ही सदाबहार पुष्प सिंहासन (गुलदाउदी) पर बैठे नये सम्राट नारूहितो ने जापान में एकता के सूत्र को अपनाते हुए एक नये युग का प्रारंभ किया.

सम्राट नारूहितो ने इंग्लैंड में अवस्थित ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है, तथा उनकी पत्नी साम्राज्ञी मसाको ने भी अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा हासिल की है. वे जापान के ऐसे पहले सम्राट हैं, जिनका जन्म दूसरे विश्वयुद्ध के बाद हुआ और पश्चिमी तौर-तरीकों तथा शिक्षा में निष्णात हैं. अपने पूर्वजों की तुलना में वे युवा तथा बेहद प्रगतिशील विचारों के धनी हैं. आज के समय में जब जापान आर्थिक मंदी, घटती जन्म दर, बूढ़े लोगों की बढ़ती संख्या तथा महिला-पुरुष भेद जैसी समस्याओं से गुजर रहा है, सम्राट नारूहितो पर जापान के लोगों की बहुत आशाएं टिकी हुई हैं.

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद 1945 तक जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराकर उसे परास्त किया, वहां के सम्राट को देवस्वरूप माना जाता था. उस हमले से हुई जापान में तबाही तथा पराजय से टूट चुके सम्राट हीरोहितो ने दैवी रूप का प्रभामंडल हटाने की घोषणा कर दी. जापान को नये सिरे से बनाने का काम तथा टूटते मनोबल को उठाने की जिम्मेदारी हीरोहितो तथा उनके बेटे राजकुमार अकिहितो ने संभाली. हिरोशिमा का घाव मिटना मुश्किल था. अमेरिका ने जापान का नया संविधान कुछ इस प्रकार बनवाया कि सम्राट के पास सिर्फ दिखावटी संवैधानिक अधिकार रहे. फिर भी जापानी जनता के मन में अपने सम्राट के प्रति सम्मान और उनकी महानता का बोध तनिक भी कम नहीं हुआ. जापान पुनः उद्योग, व्यापार, चिकित्सा तथा प्रत्येक नागरिक को उन्नति और समृद्धि का अवसर देने में विश्व में शिरोमणि बना.

एक करोड़ तीस लाख की आबादी वाला जापान, लगातार भूकंपों को झेलनेवाला जापान और चीन से आक्रामक तेवर भी संभालनेवाला जापान केवल आत्मरक्षा के लिए सेना रख सकता है. लेकिन, जापान की प्रति व्यक्ति आय और औसत आयु विश्व में सर्वोपरि है. 'मेड इन जापान' का अर्थ आज भी दुनिया में सर्वाधिक विश्वसनीय तथा दीर्घकालिक और बिना किसी तकलीफ के चलनेवाले उत्पादों के लिए जाना जाता है.

भारत-जापान संबंध सम्राट नारूहितो के काल में और बेहतर बनेंगे. यह स्वाभाविक विश्वास है, क्योंकि जापान के साथ भारत के संबंध व्यापार, राजनीति और कूटनीति से परे पारस्परिक विश्वास तथा धार्मिक, लोकतांत्रिक और सभ्यतामूलक सूत्रों के साझेपन से सिंचित हैं. जापान का बहुसंख्यक समाज शिंतो धर्म को मानता है, जो हिंदू धर्म से बहुत कुछ मिलता-जुलता है. पुनर्जन्म, माता-पिता का सम्मान और पारिवारिक मूल्य, वर्ष में एक बार पितरों का स्मरण और उन्हें पुण्यांजलि, प्रकृति की पूजा जैसे संस्कार शिंतो धर्म में बहुत गहराई से विद्यमान हैं. भारत की फिल्मों में भी विभिन्न रूपों और प्रकारों से जापान बड़ी आत्मीयता के साथ अभिव्यक्त होता रहा है. तमिलनाडु के महान अभिनेता रजनीकांत जापान के बहुत लोकप्रिय हीरो माने जाते हैं और उनका वहां बड़ा आदर है. बौद्ध मत जिन भारतीय भिक्षुओं के माधयम से जापान में प्रसारित हुआ, उनकी स्मृति में क्योटो के पास एक विशाल मंदिर है तथा आज भी वहां सरस्वती तथा गणपति की पूजा होती है.

भारत में जापानी सहयोग से सुजुकी मोटर्स ने संजय गांधी के साथ मारुति कार बनाना शुरू किया और हम सभी यह बात अच्छी तरह मानते हैं कि मारुति 800 ने भारत की सड़कों का नक्शा ही बदल दिया. दिल्ली सहित अनेक प्रदेशों में मोटर वाहन और रेलगाड़ियां जापान की ही देन हैं, तो वहीं भारत की पहली बुलेट ट्रेन भी पूर्णतया जापानी सहयोग से ही निर्मित हो रही है. नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा क्रांतिकारी रासबिहारी बोस जापान के सामान्य जन के भीतर बेहद आदर और सम्मान के साथ याद किये जाते हैं. हमारे लिए यह कितने गौरव की बात है. नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान की सहायता से ही अंडमान-निकोबार आजाद करवाया था और उसका नाम शहीद और स्वराज रखा था.

जापान के साथ वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के मध्य असाधारण आत्मीय संबंधों ने एक नया अध्याय प्रारंभ किया. जापान यात्रा के समय नरेंद्र मोदी तत्कालीन सम्राट अकिहीतो से राजमहल में विशेष चर्चा के लिए आमंत्रित किये गये थे. नरेंद्र मोदी ने जापान में एक सशक्त और अत्यंत विश्वसनीय आत्मीय मित्र के नाते बहुत गहरी छाप छोड़ी है, जिसके परिणामस्वरूप रक्षा क्षेत्र में जापान के साथ वार्षिक मलाबार सैन्य अभ्यास, और नागरिक परमाणु सहयोग संभव हो पाया है.

जापानी फिल्मों के महानायक अकिरा कुरोसोवा, यासुजिरो तथा ताकाशी शिमीजु ने सत्यजीत रे और गुरुदत्त जैसे भारत के महान निर्देशकों को खूब प्रभावित किया था.

जापान से आज हमारे जिस तरह के संबंध हैं, वैसे शायद ही किसी अन्य देश से हों. सम्राट नारूहितो जापान की सामान्य जनता के महानायक और पूजित प्रतीक हैं. जापान में सम्राट जीवनपर्यंत पद पर बने रहते हैं. केवल सम्राट अकिहीतो ही पिछले दो सौ साल में पहले ऐसे सम्राट हुए, जिन्होंने अपने जीवन काल में ही सिंहासन त्यागा. सम्राट नारूहितो के साथ भारतीय जनता और विचारकों के संबंध प्रगाढ़ हों, यह हमारे राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों के बढ़ने से भी ज्यादा जरूरी है.

किसान नहीं पेप्सिको है दोषी

डॉ अश्विनी महाजन
एसोसिएट प्रो, डीयू
ashwanimahajan@rediffmail.com

पेप्सिको को समझना चाहिए कि भारत के कानून उसके लिए बदलेंगे नहीं, खुद पेप्सिको को ही बदलना पड़ेगा. वह किसानों को बाध्य नहीं कर सकती कि वे आलू उसी को बेचें. हां, यदि पेप्सिको आलू खरीदना चाहती है, तो वह किसानों को बेहतर कीमत देकर खरीद सकती है.

विदेशी कंपनियों द्वारा भारत के किसानों से मुनाफा वसूली नयी बात नहीं है. बीटी कपास के बीज पर बिना पेटेंट अधिकार के मोनसेंटो नामक अमेरिकी कंपनी द्वारा भारत के किसानों से सात हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा रॉयल्टी की वसूली अभी तक की जा चुकी है. अब नया मसला पेय पदार्थ, आलू चिप्स और अन्य प्रकार के स्नैक्स बनानेवाली कंपनी पेप्सिको से जुड़ा है. गौरतलब है कि एफसी-5 नाम की एक आलू की किस्म की 'ठेका खेती' यह कंपनी कुछ राज्यों में किसानों से करवाती है. कंपनी के ठेका अनुबंध के अनुसार, किसानों से एक निश्चित कीमत पर एफसी-5 किस्म के आलू उगवाये जाते हैं, जिन्हें ये किसान पेप्सिको की हिदायत के अनुसार उन आलू चिप्स निर्माताओं को बेचते हैं, जिनसे पेप्सिको आलू चिप्स खरीदती है. फिर पेप्सिको द्वारा पूरे भारत में आलू चिप्स का विपणन किया जाता है. यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जाना-पहचाना मॉडल है. जाहिर है कि पेप्सिको कंपनी इस प्रकार से मोटा मुनाफा कमाती है, क्योंकि जो आलू पांच रुपये किलो से भी कम कीमत पर किसानों से खरीदे जाते हैं, मगर उपभोक्ताओं को सैकड़ों रुपये किलो के हिसाब से आलू चिप्स बेचकर कंपनियां मोटा मुनाफा कमाती हैं.

गुजरात के कुछ किसानों के खेत में जासूस भेजकर पेप्सिको कंपनी ने उन किसानों से आलू लेकर उनकी जांच करवाकर 11 किसानों पर मुकदमा कर दिया कि ये किसान कंपनी की एफसी-5 किस्म के आलू उगा रहे हैं, जिसके बीज को इन किसानों ने पंजाब के उन किसानों से खरीदा है, जिनका पेप्सिको के साथ अनुबंध था. कंपनी का आरोप है कि इस बीज को कंपनी ने पंजीकृत करवाया हुआ है, इसलिए किसानों ने कंपनी के बौद्धिक संपदा अधिकारों का हनन किया है. पेप्सिको ने अहमदाबाद, गुजरात की व्यावसायिक अदालत में मुकदमा दाखिल कर किसानों द्वारा उत्पादन पर रोक लगाने की मांग तो की ही, साथ ही चार किसानों पर उसके बौद्धिक संपदा अधिकारों के हनन की एवज में प्रत्येक से 1.05 करोड़ के हर्जाने की वसूली हेतु भी मांग की. विडंबना देखिये कि अदालत ने किसानों के खिलाफ फैसला भी दे दिया.

बौद्धिक संपदा कानूनों के जानकार का मानना है कि व्यावसायिक अदालत ने सही निर्णय नहीं दिया, क्योंकि वास्तव में किसानों ने किसी भी प्रकार से कंपनी के बौद्धिक संपदा अधिकारों का हनन किया ही नहीं. भारत के बौद्धिक संपदा कानूनों के अनुसार, वास्तव में बीज और पादप के संबंध में पेटेंट कानून लागू नहीं होता. इसके संबंध में एक दूसरा कानून है, जिसे पादप किस्म एवं किसान अधिकार संरक्षण (पीपीवीएफआर) अधिनियम, 2001 के नाम से जाना जाता है. इस कानून के हिसाब से कोई व्यक्ति अथवा व्यावसायिक इकाई किसी बीज अथवा पादप किस्म का पंजीकरण करा सकती है और किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यावसायिक इकाई को उस किस्म के उत्पाद को उस नाम (ब्रांड) से बेचने का अधिकार नहीं होगा. लेकिन इस कानून की धारा 39(1)(IV) में किसानों के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है. इस धारा के अनुसार, 'एक किसान को इस अधिनियम के तहत संरक्षित एक किस्म के बीज सहित अपने खेत की उपज को बचाने, उपयोग करने, बोने, पुनः बोने, आदान-प्रदान करने, साझा करने या बेचने का हकदार माना जायेगा, क्योंकि वह इसके लागू होने से पहले हकदार था.' गौरतलब है कि इस बात की जानकारी कंपनी को पहले से थी.

प्रश्न है कि कंपनी ने जानबूझ कर किसानों पर मुकदमा क्यों ठोका. कारण स्पष्ट है कि किसान अपने अधिकारों के अनुसार आलू पैदा कर बेच रहे हैं, लेकिन कंपनी अपनी आर्थिक ताकत के गरूर में है कि वह मुकदमा करके गरीब किसानों को डराकर उन्हें अपने साथ अनुबंध करने के लिए मजबूर कर सकती है. यह बात अदालत में स्पष्ट भी हो गयी, जब कंपनी के वकील ने प्रस्ताव रखा कि वह अपना मुकदमा वापस ले लेगी, यदि किसान उसके साथ अनुबंध करके कंपनी को ही अपने आलू बेचने के लिए तैयार हो जायें. मुकदमे की अगली तारीख जून में है. किसानों ने कहा है कि उन्हें इस बाबत समय दिया जाये.

देशभर में पेप्सिको के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है कि यह कंपनी अपने लाभ के लिए किसानों को गलत मुकदमे में घसीट रही है. गुजरात सरकार ने भी कहा है कि वह किसानों के समर्थन में खड़ी है. जब यह कंपनी चारों तरफ से घिर गयी, तो इसके मुख्यालय द्वारा कंपनी के स्थानीय अधिकारियों को हिदायत दी गयी कि जल्दी से कंपनी किसानों के साथ समझौता कर ले, ताकि जनता के गुस्से से बचा जा सके. वहीं, कुछ लोग यह भी कहते हैं कि एफसी-5 किस्म को विकसित करने में कंपनी ने लाखों डॉलर खर्च किये हैं, इसलिए उसे मुनाफा वसूली का अधिकार है. उन्हें पता नहीं है कि एफसी-5 किस्म का जो पंजीकरण पेप्सिको द्वारा किया गया है, वह एक 'एक्सटेंट वेरायटी' यानी पहले से उपलब्ध किस्म के रूप में किया गया है. ऐसे में कानूनी रूप से ही नहीं, बल्कि नैतिक रूप से भी कंपनी का यह मुकदमा कमजोर है.

किसी भी विदेशी कंपनी को उस देश के कानूनों को मानना पड़ता है. पेप्सिको को समझना चाहिए कि भारत के कानून उसके लिए बदलेंगे नहीं, खुद पेप्सिको को ही बदलना पड़ेगा. वह किसानों को बाध्य नहीं कर सकती कि वे आलू उसी को बेचें. हां, यदि पेप्सिको आलू खरीदना चाहती है, तो वह किसानों को बेहतर कीमत देकर खरीद सकती है.

आपके पत्र

मसूद वैश्विक आतंकवादी घोषित

10 साल के जद्दोजहद के बाद अंततः मसूद अजहर को, राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद् द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया. भारत के लिए यह उपलब्धि है भी और नहीं भी. चीन सुरक्षा परिषद् के शेष 14 स्थायी सदस्यों के दबाव में आकर अजहर का बचाव नहीं कर सका. इस घोषणा के बाद मसूद का विदेशी दौरा बंद हो जायेगा. विदेशों में बैंक एकाउंट्स को फ्रीज करने की बात है, तो वहां से सारा फंड वह पहले ही ठिकाने लगा चुका है. जिस देश में वह रह रहा है, वहां का प्रशासन अगर उसका साथ देता रहेगा, तब तक उसे कुछ नहीं होगा. वह अपना अलगाववाद जारी रखेगा. अक्तूबर 2001 में राष्ट्र संघ ने, दिसंबर 2001 में अमेरिका ने जैश-ए-मोहम्मद को प्रतिबंधित किया. इससे हुआ क्या? इसने अपना नाम बदल लिया. इस पर भी दबाव पड़ा तो एक ट्रस्ट के नाम से काम करने लगा. पिछले 18 सालों से इसने भारत के नाक में दम कर रखा है.

जंग बहादुर सिंह, गोलपाहड़ी,जमशेदपुर

घटता मतदान चिंता की बात है

पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस लोकसभा चुनाव का मतदान सरकार और चुनाव आयोग के कई अच्छे प्रयासों के बाद भी कम है जो दुख और चिंता की बात है. यही नहीं दुर्भाग्य से नोटा भी बढ़ता जा रहा है. लोगों की इस बढ़ती उदासीनता का कारण पार्टियों और नेताओं के झूठे वादे और व्यक्तिगत घटिया और घिनौने आरोप और बयान ही हैं. नेताओं और पार्टियों की इस कदर गिरावट बड़े दुख और चिंता का विषय है, ऐसे में ये लोग देश की क्या सेवा, सुधार और भला कर पायेंगे, सोचने की बात है. सेवा और सादगी की बात, तो प्रायः सभी करते हैं. मगर असलियत किसी से छुपी नहीं है. ऐसे में यह स्वाभाविक ही है. सबसे बड़ी समस्या तेजी से बढ़ती बेरोजगारी और जनसंख्या पर दुर्भाग्य से कतई किसी का कोई ध्यान ही नहीं है, जबकि आज काम की कोई कमी नहीं है और इनको आपस में जोड़ना भी अब बहुत जरूरी है. यदि अब भी ऐसा नहीं हुआ तो हालात और बिगड़ेंगे.

वेद मामूरपुर, नरेला

आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता

कुछ लोग इस देश में धार्मिक और जातीय नफरत के बीज बो रहे हैं. यह किसी भी नक्सली या पाकिस्तानी या आइएसआइएस आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक है. देश का हर मुसलमान गद्दार और देशद्रोही नहीं है. आतंकी का कोई धर्म नहीं होता. वे पूरी मानवता के दुश्मन होते हैं. अभी गढ़चिरौली में 15 पुलिसकर्मियों सहित 16 लोगों को नक्सलियों ने आरडीएक्स से उड़ा दिया, श्रीलंका में कई सौ लोगों को प्रार्थना सभा में फिदायीन हमले में बमों से चिथड़े उड़ा दिये गये. उससे पहले न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में पचासों लोगों को इबादत करते समय गोलियों से उड़ा दिया गया. ये उदाहरण यह दर्शाते हैं कि आतंकवादी किसी एक धर्म विशेष में ही नहीं पैदा होते. इसलिए धर्म के ठेकेदारों और राजनीति के ठेकेदारों के चंगुल में नहीं फंसें. वास्तव में ये लोग भेड़ की खाल ओढ़े भेड़िए हैं.

निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद

बोधि वृक्ष

मन का कोना

एक फकीर अकबर से मिलने गया था. उसके मित्रों ने उससे कहा था कि अकबर से कहो कि यदि वह इतना तुम्हें प्रेम करता है, तो हमारे गांव में एक छोटा सा स्कूल खोल दे. वह फकीर जब पहुंचा तो अकबर सुबह की नमाज पढ़ रहा था. नमाज पूरी हुई, अकबर ने दोनों हाथ उठाये और कहा कि हे परमात्मा! मेरे राज्य को और बड़ा कर, मेरे खजानों को बड़ा कर, मेरे धन-दौलत को बढ़ा. वह फकीर हैरान हो गया. उसने कल्पना न की थी कि अकबर भी मांगता होगा. वह वापस लौटने लगा सीढ़ियों से, अकबर उठा तो उसने देखा और पूछा कि कैसे आये और कैसे वापस लौट चले? उस फकीर ने कहा: मैंने सोचा मैं बादशाह से मिलने जाता हूं, पाया कि यहां भी एक फकीर बैठा है. जो खुद ही मांगता है उससे और मांगकर लज्जित करना शोभा नहीं देता. अगर मांगना ही होगा, तो हम भी उसी परमात्मा से मांग लेंगे. अकबर भी मांगता है. सम्राट भी मांगते हैं. इसलिए दुनिया में दो तरह के भिखारी होते हैं, एक जिनके पास कुछ नहीं होता और मांगते हैं और एक जिनके पास सब होता है फिर भी मांगते हैं. लेकिन भिखारी होने में कोई फर्क नहीं होता है. हो सकता है कि बहुत कुछ आपके पास हो, इससे इस भ्रम में न पड़ जायें कि आपके भीतर का भिखमंगा मर गया. भीतर का भिखारी समाप्त ही नहीं होता. मन मांगे चला जाता है. क्यों मांगे चला जाता है? और जो भी मिलता है उससे पूर्ति क्यों नहीं होती? क्या है बात? इतना इकट्ठा कर लेते हैं फिर भी मन का खालीपन बना रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. आपके पास जरूर कुछ न कुछ होगा. क्या उस कुछ से आपके मन का कोई कोना भी भरा? अगर मन का कोई कोना भी भर गया हो, तो आशा बंध सकती है कि कभी पूरा मन भी भर जायेगा. जो हम इकट्ठा करते हैं, वह मन में पहुंचता ही नहीं. पहुंचेगा भी कैसे? जो भी हम इकट्ठा करते हैं वह बाहर है और मन भीतर है. भीतर और बाहर का संबंध ही क्या? यह ऐसे ही है जैसे मेरा घर खाली हो और मैं पड़ोस के घर में सामान इकट्ठा करता रहूं, तो मेरा घर इससे कैसे भर जायेगा?

आचार्य रजनीश ओशो

कुछ अलग

आम के आम

सुरेश कांत
वरिष्ठ व्यंग्यकार
drsureshkant@gmail.com

आम यों तो हमेशा आम ही रहता है, जो कि आम तौर पर उसे रहना भी चाहिए, क्योंकि आम की किस्मत में ही लिखा है आम होना, वरना वह आम होता ही क्यों? लेकिन चुनाव के समय वह एकदम से खास हो उठता है. चुनाव एक समर है, जिसे छल-फरेब से जीता जाता है.

चुनाव के दौरान आम को अचानक खास समझने का एहसास कराना ऐसा ही छल है, जिसके फरेब में वह फौरन आ जाता है और अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेता है. इससे नेता को उसके पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की जहमत नहीं उठानी पड़ती. कुल्हाड़ी अलबत्ता नेता खुद ही उसे उपलब्ध कराता है. ऐसा वह इसलिए करता है कि कहीं वह आम, जिसका कि बहुवचन अवाम यानी जनता होता है, उसके विरोधी नेता की बातों में आकर उसके द्वारा दी गयी कुल्हाड़ी अपने पैरों पर न मार बैठे. वह जानता है कि जो जनता उसकी बातों में आकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार सकती है, वह किसी दूसरे की बातों में आकर भी ऐसा कर सकती है. इससे चुनाव में इस 'चु' की 'नाव' डूब सकती है और उधर चूना लगानेवाले की पार लग सकती है. सर्वविदित है कि हर नेता चुनाव में जनता को चूना लगाकर अपनी नाव बचाता है.

पूछा जा सकता है कि चुनावी समर के 'समर' में 'स' से क्या बनता है और 'मर' से उसका क्या संबंध है? जवाब में कहा जा सकता है कि समर में, भले ही वह फिर चुनाव का समर हो या कोई और, हालांकि बनता कुछ नहीं, बिगड़ता ही बिगड़ता है, फिर भी समझने के लिए कह सकते हैं कि इसमें 'स' से 'सच' बनता है, जिसे चुनाव के समर में मरना पड़ता है. नेता चुनाव की बलिवेदी पर सच की बलि चढ़ाने के बाद ही तरह-तरह के झूठ बोलकर जनता को फुसलाता-बरगलाता है, जिन्हें चुनावी भाषा में आश्वासन कहते हैं. नेता ऐसे-ऐसे झूठ बोलता है, जिन्हें सुनकर खुद झूठ भी पनाह मांगने लगे. वह ऐसा इसलिए कर पाता है, क्योंकि जनता खुद नेताओं से झूठ बोलकर फुसलाया-बरगलाया जाना पसंद करती है. ऐसे में जो नेता ज्यादा से ज्यादा और बड़े से बड़े झूठ बोलता है, जनता उसकी मुरीद हो जाती है. सर्वथा असंभव झूठ जनता को उसका अंधभक्त बनाने का काम सर्वथा संभव कर देते हैं. अलबत्ता नेताओं द्वारा लगातार झूठ बोलने के कारण वे झूठ बड़ी जल्दी पुराने पड़ने लगते हैं, जिस कारण नेताओं को और बड़े झूठ ईजाद करते रहने पड़ते हैं. फर्क यही है कि झूठ को भी उन्हें सच का जामा पहनाकर पेश करना पड़ता है. सैंया वही बन पाता है, जो झूठों का बड़ा सरताज निकलता है. जनता झूठों के उस बड़े सरताज के सर पर ही ताज रखती है.

आम को चाहे जैसे खाया जाये, उसका तो हर हाल में मरण ही है. आम के बहुवचन अवाम के बारे में भी यही सच है. चुनाव के बाद अवाम की भी गुठली ही रह जाती है, जिसके दाम भी नेता लगाये बिना नहीं रहते.

देश दुनिया से

सूडान में जनता का विरोध प्रदर्शन

साल 1950 के दशक का उत्तरार्ध अरब अधिकारियों के राजनीतिकरण के लिए जाना जाता है. वर्ष 1957 में अली अबू नुवार ने जॉर्डन में एक असफल तख्तापलट किया था. सीरियाई अधिकारी राष्ट्रपति, सरकार या संसद की जानकारी के बिना 1958 में काहिरा चले गये. वहां, उन्होंने गमाल अब्देल नासर के साथ 'एकता' नामक यथास्थिति लागू करने पर सहमति जतायी. वहीं अब्दुल करीम कासिम और अब्दुल सलाम आरिफ ने भी इराक से राजशाही को उखाड़ फेंकने के लिए तख्तापलट किया. सूडान में स्थिति अलग थी. आजादी के दो साल बाद इब्राहिम अब्दू का 1958 का तख्तापलट किसी विचारधारा से प्रेरित नहीं था. यह स्थिति, प्रधानमंत्री अब्दुल्ला खलील की सरकार में राजनीतिक दलों के आम सहमति तक नहीं पहुंचने से उपजी थी. खलील सहित राजनीतिक नेताओं को जुबा निर्वासित कर दिया गया. सेना से उसकी शक्तियां छीन ली गयीं, मजदूर यूनियनों को भंग कर दिया गया और हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया. इसके पीछे कोई विचारधारा नहीं थी. मिस्र के साथ सूडान की छह-दशक लंबी एकता ने इसमें मदद की थी. अन्याय के खिलाफ हमेशा सूडानी जनता खड़ी रही है और फिर एक बार वह विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर है.

हाजेम साघलेह

कार्टून कोना

साभार : बीबीसी

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 3, डेकर्स लेन, पहला तल्ला, कोलकाता-69 . **फैक्स करें** : 033-22100178
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर इ-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो . लिपि रोमन भी हो सकती है